भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.488
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

ग्रामीण क्षेत्रों में 5जी की शुरुआत

488. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में 5जीआई प्रौद्योगिकी के साथ 5जी की शुरुआत करने और उसके चरणबद्ध ढंग से विस्तार किए जाने संबंधी अनुमति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य सटीक कृषि, दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसे अनुप्रयोगों के लिए इंटरनेट की तीव्र गति प्रदान करना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीकी सहायता और योजना का ब्यौरा क्या है, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से पूरे देश को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने में सहायता करेगी?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी नेटवर्क शुरू किए गए हैं और वर्तमान में देश के 99.9% जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, देश में 5.08 लाख 5जी बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएसएस) पहले ही संस्थापित किए जा चुके हैं और ये बीटीएस सटीक कृषि, दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन आदि जैसे एप्लीकेशंस के लिए तीव्र गति के इंटरनेट के प्रावधान में भी सहायक हैं।

(ख) सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वर्ष 2022 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी।

ii. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी) और ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।

iii. वर्ष 2022 और उसके बाद की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार को हटाना।

iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) के लिए मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण।

v. आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की मंजूरी के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल और आरओडब्ल्यू नियमों को लॉन्च करना।

vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति।

vii. देश में 6जी तैयार शैक्षणिक और स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के निर्माण के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक 5जी यूज केस और क्षमता निर्माण के विकास के लिए पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5जी लैब्स की स्थापना की गई।

****